

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 28, 1939 शक सम्वत्) [संख्या—07

विषय—सूची प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	_	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण,		
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	107—113	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको		
उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विमागों के		
अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	139—149	1500
भाग 2—आज्ञाए, विज्ञप्तिया, नियम और नियम विघान, जिनको केन्द्रीय		
सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई		
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे		
राज्यों के गजटों के उद्धरण	_	975
माग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड		
एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा		
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों		
अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	61-62	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	·	975
भाग ५-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	_	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए		
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों		
की रिपोर्ट	· <u>-</u>	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य		
निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	_	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	51-57	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	· 	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

नियुक्ति / विज्ञप्ति

09 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 22 / XI / 18 / 53(56)2010—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा चयनित / संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय, खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान ₹ 56,100—1,77,500, लेवल 10) में कॉलम—4 में अंकित जनपद में कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए, दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

विश्व करत रु.—			
क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री / श्रीमती / कु0)	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1.	विमल रावत	देहरादून	पिथौरागढ़
2.	अमित	टिहरी गढ़वाल	चम्पावत
3.	रवि कुमार सैनी	देहरादून	अल्मोडा
4.	मुकुल नौटियाल	देहरादून	बागेश्वर
5.	असित आनन्द	देहरादून	पिथौरागढ़
6.	हेमन्त कोटियाल	देहरादून	पिथौरागढ़
7.	ललित कुमार महावर	देहरादून	अल्मोड़ा
8.	मानस मित्तल	देहरादून	पिथौरागढ़
9.	संतोष जेठी	पिथौरागढ़	पौड़ी
10.	कमल किशार पाण्डेय	पिथौरागढ	उत्तरकाशी
11.	आलोक गार्ग्य	रूद्रप्रयाग	अल्मोडा
12.	प्रवीण भट्ट	देहरादून	पौड़ी
13.	श्रुति वत्स	हरिद्वार	उत्तरकाशी
14.	शाकिर हुसैन	हरिद्वार	अल्मोड़ा
15.	सोनम गुप्ता	देहरादून	टिहरी
16.	आलोक मण्डारी	उत्तरकाशी	बागेश्वर
17.	अभिषेक सिंह ह्यॉकी	पिथौरागढ़	चमोली
18.	जय प्रिया आर्य	हरिद्वार	टिहरी
19.	अपर्णा बहुगुणा	टिहरी गढ़वाल	पौड़ी
20.	दृष्टि आनन्द	देहरादून	उत्तरकाशी
21.	अतिया परवेज	हरिद्वार	पौड़ी

નાન દી	0000 100, 17 1000, 2	010 40 (11 1 ==) 1===	<u> </u>
1	2	3	4
22.	सुमन लता	चमोली	पौड़ी
23.	रीना	टिहरी गढ़वाल	पौड़ी
24.	प्रतिमा सिंह	देहरादून	चमोली
25.	जगत सिंह	ऊधमसिंह नगर	चमोली
26.	अंकित कुमार चन्याल	नैनीताल	रूद्रप्रयाग
27.	नीतू शाह	पौड़ी गढ़वाल	चमोली
			<u> </u>

- 2. उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों की विकास खण्डों में तैनाती सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
- उक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की नीति के अधीन प्रसारित सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।
- 4. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय—समय पर स्वीकृत महंगाई मत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 5. उक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त तथा चरित्र एवं जाति प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के सकारात्मक होने के प्रतिबन्धाधीन की जा रही है। अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त तथा चरित्र एवं जाति प्रमाण—पत्रों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।
- 6. उक्त नियुक्तियाँ मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन (PIL) संख्या—67/2011, रिट याचिका संख्या—61/2016, रिट याचिका संख्या—05/2016, रिट याचिका संख्या—90/2016, रिट याचिका संख्या—438/2015, रिट याचिका संख्या—71/2014, रिट याचिका संख्या—76/2015, रिट याचिका संख्या—81/2015, रिट याचिका संख्या—95/2015, रिट याचिका संख्या—83 (एस०बी०)/2015, रिट याचिका संख्या—96 एस०बी०)/2015, रिट याचिका संख्या—105 (एस०बी०)/2015 एवं रिट याचिका संख्या—477 (एस०बी०)/2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित रिट याचिकाओं तथा रिट याचिका संख्या—442/2017 (एस०एस०) स्विप्तल मुयाल बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- उक्त नवनियुक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ निम्न प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान सूचना प्रस्तुत की जायेगी:-
 - (1) अपनी चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र।
 - (2) विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी / पति न होने का घोषणा-पत्र।
 - (3) शैक्षिक योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र।
 - (4) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- 8. उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से, मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग—1 विज्ञप्ति/नियुक्ति

11 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 1428 / XIX-1/17-70/2013—उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा की गई संस्तुति तथा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 328/XXX(2)/2017/30(57)/14, दिनांक 27.10.2017 के क्रम में श्री मुकेश पुत्र श्री चन्द्रबान, निवासी प्लॉट नं0-116, 117, आश्रम रोड, गाँव—बुढपुर, पो०ऑ०-अलीपुर, नई दिल्ली को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड-03, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 (7वं वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में ₹ 56,100-1,77,500/-) में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- प्रश्नगत सेवाएँ उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) समूह "क" एवं "ख" सेवा नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।
- 2. श्री मुकेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- उ. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि नियुक्ति के उपरान्त भी श्री मुकेश के चिरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा प्रमाण—पत्रों के सत्यापन सकरात्मक नहीं होता है और स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है, तो पिरिवीक्षाकाल समाप्त करते हुए, सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।
- 4. जिला पूर्ति अधिकारी को वेतन बैण्ड-03, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में ₹ 56,100-1,77,500/-) में तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6. आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर श्री मुकेश अपनी योगदान आख्या आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय), खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा श्री मुकेश की तैनाती आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् पृथक से निर्गत किया जायेगा। यदि उक्त अविध तक श्री मुकेश अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो यह समझा जायेगा कि श्री मुकेश उक्त सेवा में योगदान करने के इच्छुक नहीं है एवं आपका अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- श्री मुकेश को नैनीताल प्रशिक्षण अकादमी द्वारा आगामी प्रशिक्षण तिथि निर्धारित होने पर तद्नुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:—
 - (1) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा—पत्र।
 - (2) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
 - (3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - (4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

- (5) लिखित रूप में एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिलेखों के सत्थापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो श्री मुकेश की यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। जिसके लिए यह किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र।
- (7) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
- 9. यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन (PIL) संख्या—67/2011, रिट याचिका संख्या—61/2016, रिट याचिका संख्या—05/2016, रिट याचिका संख्या—90/2016, रिट याचिका संख्या—438/2015, रिट याचिका संख्या—71/2014, रिट याचिका संख्या—76/2015, रिट याचिका संख्या—81/2015, रिट याचिका संख्या—95/2015, रिट याचिका संख्या—83 (एस०बी०)/2015, रिट याचिका संख्या—105 (एस०बी०)/2015 एवं रिट याचिका संख्या—477 (एस०बी०)/2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित रिट याचिकाओं तथा रिट याचिका संख्या—442/2017 (एस०एस०) स्विनल मुयाल बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—1 प्रोन्नित / विज्ञप्ति 12 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 71/XXXI(1)/2018/पदो0-02/17-उत्तराखण्ड सिववालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसिवव, वेतनमान-लेवल 11 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) श्री बलवन्त सिंह भाकुनी
- (2) श्री हरीश चन्द्र
- (3) श्री मदन सिंह
- (4) श्री हरीश सिंह बिष्ट
- 2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 3. उक्त प्रोन्नित मां0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य, मां0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मां0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मां0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0बी0)/2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 272 (एस0बी0) 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, लित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य तथा मां0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ०प्र० में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मां0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मां0 उच्च न्यायालय की

खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ०प्र0 राज्य व अन्य व विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

- 4. उक्त रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों के क्रम में, यदि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी, संवर्ग की विरष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - 5. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किए जायेंगे।

आज्ञा से, हरबंस सिंह चुघ, प्रमारी सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड (अधिष्ठान अनुभाग) विज्ञप्ति

विज्ञान्त

19 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 117 / वि0स0 / 124 / अधि0 / 2001 – वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड – 2, भाग – 2 से 4 के मूल नियम – 56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री जगदीश चन्द्र, सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, जिनकी जन्मतिथि 06.06.1958 है, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

जगदीश चन्द्र, सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2876/XXXX/2017—37/2014—उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 में विहित व्यवस्थानुसार शासन के पत्र संख्या 999/XXXX/2017—37/2014, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून की कार्यपरिषद् का गठन किया गया है। उक्त परिनियमावली, 2015 के नियम—19(1)(इ) के प्राविधानानुसार मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा नामित मा0 जस्टिस श्री इरशाद हुसैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

हरबंस सिंह चुघ, प्रभारी सचिव।

सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) विज्ञप्ति

23 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 22199—205/डीटीईयू/ई—06/0711/02/अधि0 क्षेत्र/13—सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959, नियमावली, 1960, नियम—7 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियम व धारा के अन्तर्गत पूर्व में प्रसारित समस्त विञ्चप्तियों को निरस्त करते हुए, मैं, जीवन सिंह नागन्याल, निदेशक, सेवायोजन, उत्तराखण्ड निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अधिक्षेत्र के सेवायोजकों के सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 (संख्या 31, 1959) की धारा—6 में अमिदिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने का प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान करता हूँ:—

क्रमाक	अधिकारी का पदनाम	अधिक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
1.	उप निदेशक (सेवायोजन), उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
2.	सहायक निदेशक (सेवायोजन) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	तदेव
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लैंसडोन	जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग क्षेत्र
5.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र
6.	जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल	सम्पूर्ण जनपद नैनीताल
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पिथौरागढ़	सम्पूर्ण जनपद पिथौरागढ़
8.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चम्पावत	सम्पूर्ण जनपद चम्पावत
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सम्पूर्ण जनपद ऊधमसिंह नगर
10.	जिला सेवायोजन अधिकारी, बागेश्वर	सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर
11.	जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी	सम्पूर्ण जनपद टिहरी
12.	जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी	सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी
13.	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार
14.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चमोली	सम्पूर्ण जनपद चमोली
15.	जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण जनपद रूद्रप्रयाग
16.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
17.	नगर सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी	तहसील क्षेत्र पौड़ी
18.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रानीखेत	तहसील क्षेत्र रानीखेत
19.	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	तहसील क्षेत्र काशीपुर
20.	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	तहसील क्षेत्र हल्द्वानी
21.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रामनगर	तहसील क्षेत्र रामनगर
22.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ठ सेवायोजन कार्यालय (जनजाति), कालसी	सम्पूर्ण चकरौता तहसील क्षेत्र
23.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ठ सेवायोजन कार्यालय (विकलांग), देहरादून	देहरादून जनपद क्षेत्र

जे0 एस0 नागन्याल, निदेशक।

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०७ हिन्दी गजट/७७-भाग १-२०१८ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 28, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

01 नवम्बर, 2017

01 नवम्बर, 2017 ुई0

संख्या 5085/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनाक 17.09.2017 को वाहन संख्या यूके—10टीए—0026, मैक्सी कैब का चालान, वनवे में गलत साईड से वाहन ले जाने (खतरनाक ड्राईविंग) के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विजय राम मिश्रा पुत्र श्री शान्ति प्रसाद, दिवाली, डुण्डा, उत्तरकाशी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके—1020080002294 जो कि हल्का परिवहन यान के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.11.2017 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिठत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 45 दिवस की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनई (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिटत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—...... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अन्हें (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

01 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिटत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—....... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5089/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 09.07.2017 को वाहन संख्या UK07CA-9425, केन्टर, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अमियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sunil Kumar S/o Sri Jai Prakash की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP3720090000941 जो कि Hapur कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 22.07.2009 से 21.07.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 22.07.2009 से 19.09.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को घ्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा—19 की उपघारा—1(एफ) सपिठत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपिनयम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा—19 की उपघारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5090/लाइसेंस/2017—सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा, दिनांक 21.04.2017 को वाहन संख्या यू०के0—07टीए—5107, कार वाहन का चालान चालक द्वारा क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जय सिंह गुसाई पुत्र श्री बी०एस० गुसाई की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०ए०—0720060195137 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 28.01.2006 से 27.01.2025 तक वैध है तथा द्वारापोर्ट वैधता दिनांक 28.01.2015 से 27.01.2018 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

01 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिठत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—...... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अन्हें (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5092 / लाइसेंस / 2017 — यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या UK08CA-4967, सिटी बस वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Unsafe Driving के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अरूण कुमार S/o श्री राजेश कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-082007002431 जो कि हरिद्वार कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.04.2007 से 29.04.2027 तक वैध है तथा द्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 30.04.2016 से 29.04.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिटत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—...... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अन्हें (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5095/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या UK07AX-8786, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री शेख अब्दुल्ला S/o श्री शेख इनायतुल्ला की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720050165134 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 23.03.2005 से 22.03.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अक्टूबर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा—19 की उपघारा—1(एफ) सपिटत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपिनयम—25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की घारा—19 की उपघारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनई (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनई (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

अक्टूबर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसघारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसघारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनई (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

01 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) संपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 5051/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या UK07Y-0100, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anwisiam S/o Sri Jameel Ahmad की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720130270686 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.09.2013 से 20.09.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांकसे तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 5052 / लाइसेंस / 2017—सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या यू0क0—07टीए—1203 वाहन का चालान मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री एम0 एल0 शाही की चालक अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0—0720090076205, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.05.2009 से 21.03.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 25.05.2009 से 12.10.2019 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

31 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 5057 / लाइसेंस / 2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK-07BH-4484, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री शिवम S/o श्री अनिल राणा की चालन अनुइप्ति संख्या UK-0720160019955 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 22.06.2016 से 21.06.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांकसेसेसेसे अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

07 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) संपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतू अन्हें (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5309/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.07.2017 को वाहन संख्या UK07AG7763, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed, Rc/lc के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Harish Ahuja S/o R. S. Ahuja की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720000035267 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.09.2000 से 24.09.2020 तक वैघ है तथा ट्रान्सपोर्ट वैघता दिनांकसेसेतक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसघारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

07 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपिठत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनई (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

07 नवम्बर, 2017 ई0

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

08 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5319/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2017 को वाहन संख्या UK07BV1078, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rohit Kumar S/o Sri Rakesh Kumar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720110162146 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 08.06.2011 से 07.06.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांकसेसेसे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

09 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5368/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 10.07.2017 को वाहन का चालान चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सुखिवन्दर सिंह पुत्र श्री ज्ञयान सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू०के0—0719980273299, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 07.01.1998 से 06.01.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 21.11.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—21 के उपनियम—25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—19 की उपधारा—1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अविध के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 28, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पन्न, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

16 जनवरी, 2018 ई0

पत्रांक 272 / ना0नि0—वि0पुन0 / 2017—18—राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 850 / रा0नि0आ0अनु—3 / 1260 / 2017, दिनांक 16.01.2018 के क्रम में जिन निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अन्तिम सूचना उत्तराखण्ड शासन से ससमय प्राप्त हो गई है और उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा रहा है, उनमें तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण की जाय तथा जिन नागर स्थानीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अन्तिम सूचना शासन स्तर से समय से प्राप्त नहीं करायी गई अपितु विलम्ब से इस अधिसूचना को जारी किए जाने की दिनांक तक प्राप्त हुई है, और इस कारण पुनरीक्षण का कार्य बाधित हुआ है। उन नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचक नामाविलयों के पुनरीक्षण का कार्य निम्न संशोधित समय—सारणी के अनुसार समयबद्धता से पूर्ण किया जाय। इस हेतु पूर्व में जारी किए गए अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे:—

	कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
	(क) नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति	17.01.2018	01 दिन
2.	कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना	18:01.2018	01 दिन
3.	प्रशिक्षण अवधि	19.01.2018	01 दिन
	(ख) संगणक द्वारा घर—घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	20.01.2018 से 04.02.2018 तक	16 दिन
	(ग) प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	05.02.2018 से 09.02.2018 तक	05 दिन
	(घ) प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	10.02.2018 से 23.02.2018 तक	14 दिन

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(ङ) निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन, निरीक्षण एवं दावे आपत्ति दाखिल करना	24.02.2018 से 05.03.2018 तक	10 दिन
(च) दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	06.03.2018 से 12.03.2018 तक	07 दिन
(छ) पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	13.03.2018 से 17.03.2018 तक	05 दिन
(ज) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	19.03.2018	01 दिन

- 2. तद्नुसार जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), जिला निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने—अपने स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार—पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे तथा समस्त मतदाताओं के रिजस्ट्रीकरण एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड की निर्देश पुस्तिका के अध्याय—3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासशोधित) के नियम—20 (1) (2) के अधीन दायर की गई है।
- 3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए, जनपद के समस्त नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामाविलयों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जायेंगे जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामाविलयाँ ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

डा0 अहमद इकबाल, जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0 नि0), चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2018 ई0 (माघ 28, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, गदरपुर (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

08 जनवरी, 2018 ई0

पत्रांक 158/यूजर चार्ज उपविधि/2017—18—नगरपालिका परिषद्, ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा—2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2016 बनाई जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रमाव पड़ने वाला हों, उनसे आपित एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार—पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपित्तयाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर को प्रेषित की जा सकेगी। वादिमयाद प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

- 1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 कहलायेगी।
- 2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होंगी।
- 3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषाएँ :

- (i) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- (ii) उपविधि से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।
- (iii) नगरपालिका से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर से हैं।
- (iv) अधिशासी अधिकारी से अभिप्रेत, उo प्रo नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।
- (v) सफाई निरीक्षक से अभिप्रेत, नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर में शासन द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यमार के लिए शासन, नगरपालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है।
- (vi) निरीक्षण अधिकारी का अमिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से है, जिन्हें समय—समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।
- (vii) नियम से अभिप्रेत, मारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या—648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है।
- (viii) अधिनियम से अभिप्रेत, उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।
- (ix) जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूलों—पौद्यों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।
- (x) जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste) का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा—कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।
- (xi) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीघे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्घारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि।
- (xii) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित, किसी अनुसंधान, क्रिया—कलापों या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

- (xiii) संग्रहण (Collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिग्रेत है।
- (xiv) कचरा खाद बनाने (Composting) एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।
- (xv) ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste) से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।
- (xvi) व्ययन (Disposal) से मूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।
- (xvii) भूमिकरण (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली घूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है।
- (xviii) निक्षालितक (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बत पदार्थ का निष्कर्ष किया है।
- (xix) नगरपालिका प्राधिकरण (Municipal authority) में, म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।
- (xx) स्थानीय प्राधिकरण (Local authority) का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।
- (xxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- (xxii) सुविधा के परिचालक (Operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, मण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने—अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों से परिवर्तन किया जाता है।
- (xxiii) पुनर्चक्रण (Recycling) से वह क्रिया अभिप्रेत हैं, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
- (xxiv) पृथ्यक्करण (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग—अलग करना अभिप्रेत है।

- (xxv) भण्डारण (Storage) से नगरीय ढोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा—करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।
- (xxvi) परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा—करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।
- 4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।
- 5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापना, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
- 6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पाद व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय—समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।
- 7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) देना होगा।
 - 8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापना द्वारा जहाँ तक सम्मव हो, बागवानी व सभी पेड़-पौघों का कूड़ा परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्घारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्घारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
 - 9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार—द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।
- 10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव—चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव—चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
- 11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई मी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
- 12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

- 13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और इसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
- 14. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।
- 15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।
- 16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक—अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है तो प्रथम बार ₹ 200.00, दूसरी बार ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 अर्थदण्ड (Penalty) देना होगा।
- 17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (Penalty) देनी होगी।
- 18. यह कि नगरीय ठोस प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् है:--

अनुसूची-1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्रम सं0	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	जैविक, अजैविक कूड़ा, अलग—अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक, अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही देने पर	जो व्यक्ति, घर/ स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देनें पर
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10	15	20	25
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4.	सब्जी एवं फल विक्रोता	100	200	100	125
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बारातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बेकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75

90	उत्तिविञ्च नजट, ।।	17 (4 (I, 2010 QU	(11-1 20, 1000 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	2	3	4	5	6
11.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	(क) फैक्ट्री (उद्योग), छोटे	200	400	300	450
	(ख) फैक्ट्री (उद्योग), मध्यम	400	700	600	900
	(ग) फैक्ट्री (उद्योग), बड़े	2000	3000	1000	1500
17.	वर्कशाप / कबाड़ी	1000	1500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य, जैसे भण्डारा, जागरण व शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की घारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 (रु० पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाए, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर में निहित होगा।

नजर अली, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गदरपुर (ऊ०सिं० नगर)। अन्जू भुडडी अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, गदरपुर (ऊ०सिं० नगर)।

सूचना

21 अप्रेल 2015 समाचार पत्र प्रकाशन के उपरान्त अपना नाम JEEWAN CHANDRA से बदलकर समस्त पहचान पत्रों में JEEWAN CHANDRA PANDEY कर लिया है। भविष्य में मुझे JEEWAN CHANDRA PANDEY नाम से जाना जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

जीवन चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व०
पूरन चन्द्र पाण्डेय
निवासी:-ग्राम-हल्दूचौड जग्गी
पोस्ट-हल्दूचौड
जिला-नैनीताल

सूचना

मेरे पति श्री आदित्य भार्गव के UTI (सीनियर सिटीजन यूनिट प्लान) में मेरा नाम एकता भार्गव घर का त्रुटि से दर्ज हो गया है, जब कि मेरा वास्तविक नाम शशी बाला भार्गव है, भविष्य में मुझे शशी बाला भार्गव नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(शशी बाला भार्गव)
पत्नी श्री आदित्य भार्गव,
निवासी-8, केशव रोड,
लक्षमण चौक, देहरादून।